Title: Need to implement measures for the welfare of the farmers in the country- laid.

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, सरकार पहली बार किसानों के लिए कुछ राहत का कार्य कर रही है और इस वर्ष के बजट में ऋण माफी की घोषणा स्वागत योग्य है। वैसे ही किसान बेहाल और फटेहाली की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर हैं। उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है। फसल तैयार होते ही बिचौलिए आ जाते हैं। एम0एस0पी0 भी उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि सरकार के खरीद केन्द्र नियमित कार्य नहीं करते। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और सुखाड़, अति वर्षा आदि से फसल ही नष्ट हो जाती हैं। खेती के लिए उन्हें पर्याप्त धन नहीं होता, क्योंकि आजकल खेती करना मंहगा होता जा रहा है। खाद, बीज, मजदूरी, डीजल आदि मंहगे हो रहे हैं। बिजली मिलती नहीं है। सिंचाई के साधन पूरे देश में नहीं के बराबर है। इस परिस्थिति में किसानों को साहूकारों का ही सहारा होता है और उनसे वे अधिक दर पर ऋण लेते हैं। वही ऋण उनके लिए जान का जोखिम हो जाता है। किसानों की आबादी आज करीब 70 प्रतिशत है और वे ही हमारे अन्नदाता हैं। उनकी यह स्थिति पूरे देश में है और खासकर गरीब राज्य जैसे बिहार में किसानों की तो स्थिति और बदतर है।

इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर सरकार किसानों को विशेष यानी टोकन ब्याज दर 2 प्रतिशत मात्र पर समुचित ऋण की व्यवस्था करनी चाहिए और वे अधिक से अधिक ऋण बिना किसी परेशानी के बैंकों और सहकारी क्षेत्र के बैंकों से ले सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। देश का किसान अगर खुश होगा और समृद्ध रहता है तो देश खुशहाल और समृद्ध बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार साथ ही साथ किसानों को उन्नत बीज, उचित मूल्य पर खाद समुचित मात्रा में उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए और फसलोपरांत उनके उपज की समुचित मूल्य मिले, यह व्यवस्था अविलम्ब करने की आवश्यकता पर ध्यान देने की कृपा करें।